

संपादकीय सिंथेटिक ट्रैक्स को तबाह मत करो

पैसों की हवस के आगे इंसान

ਮੂਰਿੰਦਰ ਸਿੰਹ

पैसों की हवस के आगे इंसान इतना गिर जाए कि जिंदा इंसानों के शरीर के अंग बेचने लग जाए? भला कौन विस करेगा कि यह भी अब उन कुछ वहशियों का कारोबारी हिस्सा है, जो बाकयदा गैंग बनाकर, सुनियोजित तरीके से लगे हुए हैं। हैरानी तब ज्यादा होती है जब इसमें देवालय सटूश्य अस्पतालों के बड़े-बड़े रुठबेदार और ओहदेदार भी हिस्सेदार होते हैं। इस अवैध धंधे में बहुत गहरी जड़ें कम समय में ऐसी जमा ली हैं कि धंधेबाज सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। भारत में भी सीमा पार तक से गुपचुप तरीके से स्वस्थ लोगों के अंगों को खरीदने-बेचने का सिलसिला तेजी से पनप रहा है। इतेफाक से कोई मामला सामने आता है तो उसकी जड़ों तक पहुंचता जांच दल हका-बका रह जाता है। कैसे, कितनी सफाई से अंगों में धूल झोंक, इतना बड़ा कांड होता रहा और भनक तक नहीं लगी? बीते हफ्ते बांगलादेश से बुलाकर जयपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले गिरोह का गुरु ग्राम में भांडाफोड़ हुआ। छापेमारी में किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके और कराने वाले डोनर, मरीज सहित 4 लोग हथें चढ़े। इनसे खुलासा हुआ कि मरीजों से 10-12 लाख रु पये वसूले जाते, जबकि डोनर को महज दो लाख बांगलादेशी टका पकड़ते। पकड़ाए बांगलादेशी किडनी डोनर शमीम ने हैरान कर देने वाली जानकारी दी। उसने फेसबुक पर किडनी डोनेट करने का विज्ञापन देखकर भारत में मुर्तजा से संपर्क साधा। उसके कई मेडिकल टेस्ट हुए। उसे कोलकाता के मेडिकल वीजा पर गुरु ग्राम में रु कवाया गया। आधार और दूसरे कई फर्जी कागज बने। पता चला कि गुरु ग्राम का बड़ा अस्पताल देख इनके जाल में लोग फंस जाते। बाद में इसी अस्पताल की जयपुर ब्रांच में ट्रांसप्लांटेशन का खेल होता। मुर्तजा झारखंड का है। लंबे समय से इस धंधे में लिप्स है। फरवरी, 2019 में कानपुर पुलिस ने एक बड़े किडनी-लीवर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह गरीब को फंसाता और दिल्ली में किडनी बिकवाता। छह लोगों गिरफ्तार हुए जिनके तार न केवल कानपुर से दिल्ली, नोएडा, बल्कि विदेशों से भी जुड़े निकले। गिरोह किडनी बेचने वाले मजबूर को 3-5 लाख रुपये बमुश्किल देता वहीं जरूरतमंद से 30 लाख रु पये से भी ज्यादा वसूलता। जांच में खुलासा हुआ कि गैंग का सरगना टीआरके राव 2016 में अपोलो हॉस्पिटल किडनी कांड में जेल जा चुका है। विडंबना कहें या कानून से बेखौफ निर्लज्जता जेल से बाहर आते ही फिर इसी गोरखधंधे में लग गया।



शक्तों से मेलों, उत्सवों व राजनीतिक रैलियों से बचे समय में चलती रही हैं। इन पुराने व ऐतिहासिक मैदानों का हाल कुछ ठीक नहीं है। कहीं अतिक्रमण व कहीं पर अव्यवस्था का बोलबाला साफ़नजर आता है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की तरकी में विभिन्न सरकारों का योगदान रहा है, मगर हिमाचल प्रदेश में पहली बार नई सदी के शुरुआती वर्षों में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल ढांचे को खड़ा करने की शुरुआत की और आज हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड एथलेटिक्स, क्रिकेट, हाकी, तैराकी व इंडोर खेलों के लिए उपलब्ध है। क्रिकेट में अनुराग ठाकुर की सोच ने हिमाचल प्रदेश को क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया है जो काबिले तारीफ है। लुहून का खेल परिसर पूर्व मंत्री ठाकुर रामलाल के प्रयत्नों से बिलासपुर में सामने आया है। एथलेटिक्स सभी खेलों की जननी है। इसी से सब खेल निकले हैं और इसके प्रशिक्षण के बिना किसी खेल में दक्षता नहीं मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में आज हमीरपुर, बिलासपुर व धर्मशाला में तीन सिंथेटिक ट्रैक बन कर तैयार हैं। शिलारू के साई सेंटर में दो सौ मीटर का प्रैक्टिस ट्रैक बन कर तैयार है। सरस्वतीनगर में काम हो रहा है।

किसी किसी राज्य के पास अभी तक एक भी ट्रैक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर व धर्मशाला सिंथेटिक ट्रैकों पर लोग टहलते नजर आते हैं। भर्ती के लिए बाहर कच्चे पर केवल ट्रायल के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। शेष ट्रेनिंग बाहर के अन्य मैदानों व सड़कों पर हो सकती है। सिंथेटिक ट्रैक पार्क बन चुके हैं। वहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए, केवल एथलीट के लिए ही प्रवेश रखना चाहिए। तभी इन प्लैफैल्ड को लंबे समय तक खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। कल जब हिमाचल प्रदेश के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट होंगे और प्रशिक्षण के लिए उखड़ा हुआ ट्रैक होगा तो फिर पहाड़ की संतानों को पिछड़ने का दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए इस बरबादी को अभी से रोकना होगा। तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों से न्याय कर सकेंगे। इस कॉलम के माध्यम से इस विषय पर कई बार लिखने के बाद भी हिमाचल सरकार इन विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। हिमाचल में ट्रेनिंग कर पहाड़ की संतानें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुछ लोगों के जुनून ने बिना सुविधाओं के मिट्टी पर ट्रेनिंग कर राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दस्तक दी थी, तभी यह अंतरराष्ट्रीय

स्तर की सुविधा आने वालों को मिल पाई है। हिमाचल प्रदेश में इस समय हर जिला स्तर सहित कई जगह उपमंडल स्तर पर भी इंडोर स्टेडियम बन कर तैयार हैं, मगर उन स्टेडियमों में बनी एवं फील्ड का उपयोग प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों को ठीक से करना नहीं मिल रहा है। वहां पर अधिकतर शहर के लाला व अधिकारी अपनी फिटनेस करते हैं। ऊना व मंडी में तरणताल बने हैं, मगर वहां पर भी कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश में तैराक ही नहीं हैं। यहां पर भी प्रशिक्षण न होकर गर्भियों में मस्ती जरूर हो जाती है। ऊना में हास्की के लिए एस्ट्रोटर्फिंची हुई है, मगर उसकी तो पहले ही दुर्गति हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार का युवा सेवाएं एवं खेल विभाग अभी तक करोड़ों रुपए से बने इस खेल ढांचे के रखरखाव में नाकामयाब रहा है। उसके पास न तो चौकीदार हैं और न ही मैदान कर्मचारी, पर्याप्त प्रशिक्षकों की बात तो बहुत दूर की बात है क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व खेल मंत्री इस बात का संज्ञान लेंगे, ताकि इन अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को बचाया जा सके। प्रदेश के पास आज से दो दशक पहले तक खेल ढांचे के नाम पर सैंकड़ों साल पहले राजा-महाराजाओं द्वारा मेले व उत्सवों के लिए बनाए गए चंद, मगर बेहतीन मैदान चंबा, मंडी, नादौन, सुजानपुर, जयसिंहपुर, कुल्लू अनाडेल, रोहड़, रामपुर, सोलन, चैल, नाहन आदि जगहों पर थे। इन मैदानों पर हिमाचल प्रदेश की खेल गतिविधियां कई दशकों से मेलों, उत्सवों व राजनीतिक रैलियों से बचे समय में चलती रही हैं। इन पुराने व ऐतिहासिक मैदानों का हाल कुछ ठीक नहीं है। कहीं अतिक्रमण व कर्हीं पर अव्यवस्था का बोलबाला साफ नजर आता है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की तरकी में विभिन्न सरकारों का योगदान रहा है, मगर हिमाचल प्रदेश में पहली बार नई सदी के शुरुआती वर्षों में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल ढांचे को खड़ा करने की शुरुआत की।

विचार

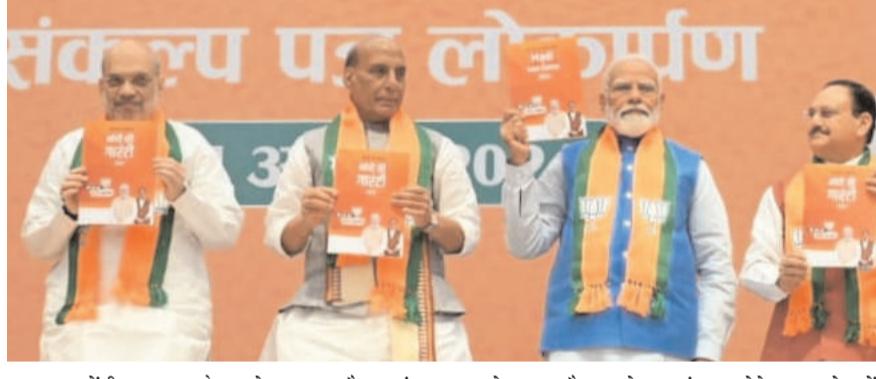
हाईकोर्ट के बेबाक फैसले से सबसे मुरिकल विपक्ष

अरविंद केजरीवाल मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के बेबाक फैसले ने कई भ्रमों को दूर कर दिया है। यही कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना गलत है। इसलिए कि वह छुटे तथ्यों और डराए गए गवाहों से बलात लिए बयानों पर आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली सरकार को जर्मीदोज के इरादे से रची गई साजिश के तहत है। यह आम चुनाव में भागीदारी के समान अवसर के अधिकार से वर्चित करना है। इनके पीछे केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार है, जिसके इशारे पर ईडी काम कर रहा है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 25 मिनट तक पढ़े गए अपने फैसले में केजरीवाल की याचिका के सभी मुद्दों को बिंदुवार स्पष्ट किया है। फैसले के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी नियमत और साक्ष्य-आधारित है। रिमांड जायज है। ईडी के आठ-आठ समनों के बाद भी पूछताछ में न आना और पर्यास सबूत भी हों तो गिरफ्तारी लाजिमी है। इसमें हैसियत के हिसाब से फेरबदल नहीं किया जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के करोड़ों रुपये के मामले में प्रमाणित सलिलता रही है। वे इससे व्यक्तिगत रूप से और बतौर आप संयोजक जुड़े रहे हैं। इसकी पुष्टि ईडी के समक्ष नहीं, बल्कि अदालत में धारा 164 के तहत गवाहों के बयानात से भी होती है। हालांकि आप नेता इन्हें ईडी का गढ़ा मान रहे हैं। उनका यह रवैया जनता को तथ्यों से गुमराह करने वाला है, चुनावी मौसम में वह चाहे जितना सही हो। यह अदालत की मान्यता के भी विरुद्ध है। हालांकि उच्च न्यायालय ने इन गवाहों से आगे मुकदमे की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के बहस के हक को नकारा नहीं है। न्यायालय का यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है कि यह मामला केंद्र नहीं बल्कि ईडी बनाम अरविंद केजरीवाल का है। यह कोई राजनीतिक नहीं, सीधे-सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। इसके आरोपित को जांच के तरीके तय करने या इसमें कोई सुविधा मांगने का हक नहीं है। उसे एक आम नागरिक की तरह ही लड़ाई लड़नी होगी। इस फैसले ने मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया है। उन्हें सहानुभूति पाने के लिए न्या तर्क गढ़ना होगा। केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती न्यायालय के इस आकलन को गलत ठहराने की होगी, जो ईडी से सहमत है कि आप एक पार्टी नहीं, बल्कि कंपनी की तरह है और वे खुद निदेशक की तरह काम करते हैं। उनके लिए फैसले का यह सबसे मुश्किल विपक्ष है। केजरीवाल अब सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं, जहां उन विवादियों पर भी पौरी किया जाएगा।

राह कैसा राम राज?

22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अयोध्या में, राम लला की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के बाद, प्रधानमंत्री जी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वैसे यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस विशाल और व्यापक आयोजन से उनका जनाधार बढ़ा है तथा वे हिंदू मानस के सर्वप्रिय नेता बन गए हैं। यहां तक की हिंदू धर्म गुरु, शंकराचार्य और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के थोक बंद ठेकेदार डॉक्टर मोहन भागवत जी, श्री नरेंद्र मोदी जी की आभा के समक्ष पीछे नजर आ रहे हैं। 4 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी गुवाहाटी के दौरे पर थे। और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 'आजादी के बाद सत्ता में रहे लोग पूजा स्थलों के महत्व को नहीं समझ सके। उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने का चलन स्थापित किया। जबकि विकास और विरासत हमारी नीति है कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा तीर्थ मंदिर सभ्यता की यात्रा की निशानियां है। हमारे तीर्थ मंदिर सिर्फ दर्शन करने की स्थली नहीं है यह हमारी सभ्यता की अमिट निशानियां है। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे उसको अटल रखा है यह उसकी साक्षी है। कोई भी देश अपने अतीत को भुलाकर या मिटाकर विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि पिछले 10 वर्षों में हालात बदल गये हैं'। उनकी आखिरी पंक्ति पर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश में जो कुछ अच्छा हुआ है वह उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में हुआ है और जो कुछ खराब हुआ है वह उनके आने के पूर्व का है, यह कहना उनके प्रारंभिक व स्थाई शगल है। एक प्रकार से वे अपने आपको शश भूतों न भविष्यती सिद्ध करते रहते हैं। उनकी आत्म प्रशंसा करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति का स्वभाव होता है। विशेषता जिन सज्जनों में योग्यता कम होती है वे दिखावे ज्यादा करते हैं। हमारी पुरानी कहावत है 'अध जल भरी' गणराया छलकत जाएँ। पर मूल प्रश्न जिस पर विचार जरूरी है कि संस्कृति पर शर्मिंदगी का चलन देश में कब था।

भाजपा अपना संकल्प पत्र-मुफ्त राशन-बिजली, यूसीसी का वादा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा.....



पायलट बनंगा । पाइप के रास्त घर-घर गेस पहुंचाए जाएंगे । हमारे लिए दल से बड़ा देश है । वर्दे भारत ट्रेन के तीन मॉडल चलेंगे । अब गरीबों को उनका अधिकार मिल रहा है और गरीबों को लूटने वाले जेल जा रहे हैं । भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, यह मोदी की गारंटी है । पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया । उन्होंने कहा कि यूसीसी देशहित के लिए आवश्यक है । पीएम मोदी ने कहा, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं । अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल जाएँ तभी उससे ज्यादा जिंदगी जाने वाले 3

कराड़ घर और बनान का सकल्प लत हुए आग बढ़ेग ।
अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर-घर पहुंचाए हैं, अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर-घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे ।

जैपी नटा द्वे कृष्णमेह पाप माधव विष्णाना - मेटी जी

चित्रांकन होगा। लेकिन हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी और जनसंघ काल से शुरू हुई एक असंबद्ध आधारित पार्टी के गुण, उन विचारों को लगातार छोड़ गए। वाद्ययत्र अधिकान की यात्रा में हम सब लोग शामिल हैं। जब-जब चुनाव आता है, तब-तब हम सब लोग उसी तरह से विस्वत यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार 2.0 की सफलता का किया जिक्र - भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा, महिला आरक्षण कानून का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, जो 30 सालों में नहीं हुआ नो 3 दिन में हो गया। संसद में महिलाओं को आरक्षण दी गई। कोराना काल के दौरान सरकार मजबूती से लड़ी। हमने अर्टिकल 370 को हटाया। आज 50 करोड़ जनधन खाते से 55.5 प्रतिशत जनधन खाता महिलाओं के नाम पर सूचीबद्ध हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे - जानकारी के मुताबिक, पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे बढ़ाने की घोषणा भी हो सकती है। अभी किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये दिए जाते हैं। इसी तरह परोक्ष तौर पर किसानों के लिए कुछ अन्य योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। सत्ता में आने पर एक ऐसे कानून बनाने का भी वादा किया जा सकता है कि जिसमें ईडी द्वारा जब्त संपत्ति के मामले में निवेशकों को जल्द पैसे वापस करने जैसी बात हो सकती है।

विपक्षी गठबंधन-कांग्रेस की प्रासंगिकता

कलदीप चंद अनिन्होळी

A high-contrast, black-and-white silhouette illustration. In the center, a figure stands on a raised platform, gesturing with their right hand as if speaking to a crowd. The crowd is represented by numerous silhouettes of people's heads and shoulders, some holding up protest signs. The word "Politics" is written in large, bold, white letters across the bottom of the image.

कर दिए हैं। लेकिन वैसे वे बराबर कह रही हैं कि वे इंडी के साथ मजबूती से खड़ी हैं और बंगाल को छोड़ कर बाकी सभी जगह उसका समर्थन कर रही हैं। लेकिन सोनिया गांधी इतना तो जानती हैं कि उनकी पार्टी को यदि ममता बनर्जी की जरूरत थी तो केवल बंगाल में थी। शेष भारत में, सोनिया गांधी तो क्या, ममता बनर्जी खुद भी जानती हैं कि उनकी हैसियत ही नहीं है। एक दूसरी पार्टी है जो इंडी गठबंधन में सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन दिखाई नहीं देती। यह पार्टी अब भारत में 'अशरीरी' हो गई है। उसका नाम मुस्लिम लीग है। यह कांग्रेस के पैदा होने के कुछ साल बाद 1905 में पैदा हुई थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस पार्टी को पैदा करने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया था। मुस्लिम लीग को पैदा करने के बाद बंगाल विभाजन को भी खत्म कर दिया था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से भारत के मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। बाद में संबंध बनते बिगड़ते गए, लेकिन कांग्रेस ने 1947 में अपनी कार्यसमिति की अंतिम बैठक में मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग का समर्थन करने के लिए

‘भारत विभाजन’ का प्रस्ताव पारित किया था। भारत विभाजन के बाद जब बचे-खुचे भारत में मुस्लिम लीग के लिए रहना मुश्किल हो गया, तो उसने अपनी शक्ति में प्लास्टिक सर्जरी करवा कर रूप बदल लिया था। उससे चेहरा तो बदल गया था, लेकिन भारत के लोग उनकी आवाज अच्छी तरह पहचानते ही हैं। इसलिए वे बराबर चिल्हा रहे हैं। यह बदल रहे चेहरे से धूम रही वही मुस्लिम लीग है जिसने भारत का विभाजन करवाया था। लेकिन सोनिया जी का कहना है कि यह पुराने वाली मुस्लिम लीग नहीं है। यह नई ताजा मुस्लिम लीग है जिसका पुरानी मुस्लिम लीग से कोई ताल्ख नहीं है। पता चला है कि कुछ पुराने कांग्रेसियों ने कान में बताया थी कि मैडम, आपको पुरानी वाली का पता नहीं है, क्योंकि आपकी पृथग्भूमि इटली की है। यह मुस्लिम लीग शत प्रतिशत पुराने वाली मुस्लिम लीग ही है। लेकिन सोनिया गांधी नहीं मानी। वह उसी को सच मानती हैं जो राहुल-प्रियंका-रावर्ट वाड़ा बताते हैं। अब यह नई वाली मुस्लिम इंडी का हिस्सा है। उसका परिणाम थी सामने आने लगा है। सोनिया जी की पार्टी ने अपना जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया

है, यदि उसको ध्यान से पढ़ा जाए, जिससे अंग्रेजी वाले 'टूरीड बिटवीन दी लाइन्ज' कहते हैं, तो वह काफ़ी हद तक 1947 से पहले का मुस्लिम लीग के चुनाव घोषणा पत्र का नया संस्करण लग रहा है। अब तबलीन सिंह का कहना है कि आधा हिस्सा कायनिस्ट पार्टी का ही है। सोनिया गांधी जी की एक दूसरी समस्या भी है। वह मुस्लिम लीग का समर्थन तो लेना चाहती है, लेकिन यह नहीं चाहती कि लोग इसको जान लें। वैसे पूछा जा सकता है कि 'गुड़ तो खाएं, लेकिन गुलगुलों से परहेज' की इस नीति का कारण क्या है। जब अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र समेट लिया, अयोध्या में राम मंदिर में आने के निमंत्रण को सार्वजनिक रूप से तुकरा दिया और मुस्लिम लीग को मंच पर भी बिठा लिया तो अब बचा क्या है? फिर यह हिचकिचाहट कैसी? यह संकट केरल के वायनाड में आया। राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश को छोड़ कर केरल चले गए हैं। केरल में भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र वायनाड को उन्होंने अपने लिए चुना है। सारे देश में उन्हें लोकसभा में जाने के लिए अपनी पार्टी की विचारधारा और उसके अनुरूप मित्रों के कारण वायनाड ही सुरक्षित लगता है। यह पांच साल पहले ही स्पष्ट हो गया था जब राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अमेठी में तुकरा दिया था और वायनाड ने उन्हें संकट के उस काल में सुरक्षा चक्र प्रदान किया था। तब बहुत से राजनीतिक विश्लेषक मानने लगे थे कि राहुल गांधी अब पांच साल मेहनत करके उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास जीतेंगे। लेकिन शायद सोनिया परिवार ने यह लंबा रास्ता अखिल्यार करने की बजाय वायनाड का सुरक्षा चक्र लेना ही उचित समझा। लेकिन इस बार एक झंझट हो गया। राहुल गांधी दिल्ली से वायनाड तक की लंबी दूरी तय करके लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वायनाड पहुंचे, तो स्वाभाविक ही मन में आया होगा कि शक्ति प्रदर्शन के लिए रोड शो भी कर लिया जाए।

